



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

भाग I—खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

8W
27/11

सं० 189] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 1989/अश्विन 13, 1911

No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1989/ASVINA 13, 1911

इस भाग में भिन्न-वृत्त संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय,

(पर्यावरण वन और वन्यजीव विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1989

संख्या 1-8/89-टी एम ए - वनीकरण और वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से देश में परती
भूमि को उत्पादन योग्य बनाने के प्रमुख उद्देश्य से बिनाक 7 मई, 1985 के संकल्प संख्या 7-22/85 एफ एम
आई (पी) के द्वारा मई 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी।

2 गत चार वर्षों की अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य का समीक्षा में देश के
मुख्य भूमि निष्काटकरण और वन विनाश की गम्भीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यापक आधार वाले
और बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2798 G1/89

(1)

3. एक समयबद्ध और बहु-पक्षी क्रियान्वयन कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है और यह आवश्यक है कि क्रियान्वयन कार्यक्रम के प्रबंध केन्द्रित तथा तर्कसंगतता की भावना से परिपूर्ण बनाया जाए।

4. तत्पश्चात्, राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा प्रौद्योगिकी मिशन के स्तर पर उसका उन्नयन करने और निम्नलिखित व्यवस्थाएँ तत्काल किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) परती भूमि विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का समन्वय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जो मिशन के सभी कार्यों के निपटारे के लिए एक मिशन निदेशालय स्थापित करेगा।

(ख) मिशन निदेशालय का अध्यक्ष एक प्रायोजन निदेशक होगा जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ग) मिशन की प्रबंध व्यवस्था का मार्गदर्शन और निरीक्षण एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा, जिनके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

(घ) मिशन को अपने कार्यकरण में प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी। इस संबंध में विस्तृत प्रवेश पृष्ठ से जारी किया जाएगा।

(ङ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का विद्यमान स्टाफ और बजट नए मिशन निदेशालय और/अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा।

महेश प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th October, 1989

No. 1-8/89-TMA—The National Wastelands Development Board was established in May, 1985, vide Resolution No. 7-22/85-FRY (P) dated 7th May, 1985, with the principal aim of bringing under productive use the wastelands in the country through a massive programme of afforestation and tree planting.

2. A review of the work done under the aforesaid programme during the last four years has brought out the need for a more broad-based and multi-disciplinary approach to deal with the serious challenge of land degradation and deforestation facing the country.

3. A time-bound and multi-pronged action programme is urgently needed and it is necessary to impart management focus and a sense of urgency to the action programme.

4. It has been accordingly decided to strengthen and upgrade the Wastelands Development Programme to the level of a Technology Mission and to make the following arrangements with immediate effect :—

- (a) The Technology Mission for Wastelands Development will be coordinated by the Ministry of Environment and Forests, which will set up a Mission Directorate to handle all work of the Mission.
- (b) The Mission Directorate will be headed by a Project Director to be appointed by the Government of India.
- (c) The Mission management will be guided and overseen by an Empowered Committee, which will be serviced by the Ministry of Environment and Forests.
- (d) The Mission will enjoy administrative and financial autonomy in its working. Detailed order in this regard will issue separately.
- (e) The existing staff and budget of the National Wastelands Development Board will be transferred to the new Mission Directorate and/or the Ministry of Environment & Forests.

MAHESH PRASAD, Secy.

